दिनांक 15.01.2018 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित योजनाओं की स्वीकृति एवं व्यय संबंधित बैठक की कार्यवाहीः–

बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। उप निदेशक (शष्य), पी0पी0एम0 द्वारा बताया गया कि आज तक कुल उद्व्यय 2402.7696 करोड़ रू0 के विरूद्ध 1831.7809833 करोड़ रूपये का स्वीकृत्यादेश निर्गत हो चुका है तथा 49.4878668 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (टी0आर0एफ0ए0) की 20.82134 करोड़ रूपये की योजना प्रक्रियाधीन है, जिसका स्वीकृत्यादेश प्रारूप उपस्थापित है। राज्य योजना अन्तर्गत कृषि शिक्षा की कुल 3.2055 करोड़ रूपये एवं किसान सलाहकार योजना की कुल 31.1040 करोड़ रूपये की योजना संबंधित मंत्रिपरिषद हेतु संलेख उपस्थापित है। कृषि विपणन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 6.69824 करोड़ रूपये की योजना संबंधित स्वीकृत्यादेश प्रारूप उपस्थापित है। कृषि ऋण पर ब्याज योजना जो 10.00 करोड़ रूपये की है तथा माप एवं तौल 1.8434868 करोड़ रूपये की योजना आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा लगाई गई आपत्ति के निराकरण के क्रम में है। मेघदूत योजना, जो 6.8401 करोड़ रूपये की है, विमर्श में हैं तथा इसके अतिरिक्त सबमिशन एण्ड सीड प्लांटिंग मैटेरियल अंतर्गत बीज प्रयोगशाला की सुदृढ़ीकरण की योजना, जो 0.8922 करोड़ रूपये की है, पर संबंधित बजट शीर्ष में उपबंध हेतु बजट पदाधिकारी को संचिका भेजी गई है।

बजट पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध निर्गत की गई आबंटन संबंधी दी गई जानकारी निम्नवत् है :–

A. <u>केन्द्र प्रायोजित योजना</u> :–

(राशि करोड़ रू0 में)

	योजना का नाम	कुल स्वीकृत राशि	कुल निर्गत आबंटन
i	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	134.49951	68.636836
ii	राष्ट्रीय तेलहन एवं ऑयलपाम मिशन	3.4474	0.8983
iii	राष्ट्रीय कृषि संधारणीय मिशन	34.70466	1.88399
iv	परम्परागत कृषि विकास योजना	27.9362	3.569036
v	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	43.85	11.6667
vi	समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम	53.3833	32.01666
vii	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	68.3333	20.83335
viii	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन	90.388516	70.0056404
ix	नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान–एग्रीकल्चर	4.2005	2.8491167
x	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	287.4115947	208.3432434
xi	सबमिशन एण्ड सीड प्लांटिंग मैटेरियल	34.3906	18.1238
	कुल	**782.5455807**	**438.8266725**

उपरोक्त स्वीकृत राशि के अनुरूप आबंटन निर्गत नहीं हो पाने का कारण पूछे जाने पर बजट पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि केन्द्रांश की विमुक्ति नहीं होने के कारण राज्यांश सहित आबंटन विमुक्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। तदोपरान्त प्रधान सचिव द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित सभी नोडल पदाधिकारियों को व्यय की प्रतिशतता बढ़ाते हुए भारत सरकार से राशि विमुक्त कराने हेतु सभी संभव प्रयास करने हेतु निदेश दिया गया तथा कृत कारवाई से अवगत कराने हेतु भी निदेशित किया गया।

B. राज्य योजना :–

(राशि करोड़ रू0 में)

	योजना का नाम	कुल स्वीकृत राशि	कुल निर्गत आबंटन
i	कृषि शिक्षा	110.8583	110.0265
ii	भूमि संरक्षण	29.9043	29.9043
iii	उद्यान विकास	80.7587	61.5414778
iv	बीज विकास कार्यक्रम	106.4664244	92.4945044
v	मिट्टी, बीज, उर्वरक, प्रयोगशाला उन्नयन कार्यक्रम	8.00	5.5899
vi	कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम	180.00	179.9999
vii	प्रसार सुदृढ़ीकरण योजना	196.3215982	152.4039774
viii	जैविक खेती उन्नयन कार्यक्रम	129.77	129.7699790
ix	डीजल अनुदान	175.00	106.6303777
x	कौशल विकास	12.00	12.00
xi	मेघदूत	14.8612	10.00
xii	बोरलॉग	0.753	
	कुल	**1044.693523**	**890.3609163**

बजट पदाधिकारी द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी से स्पष्ट है कि राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध आबंटन उपलब्ध होने के बावजूद व्यय नहीं हो पा रहा है। बीज विकास कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी, उप निदेशक (शष्य), बीज से व्यय नहीं हो पाने का कारण पूछने पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। सभी जिलों का गहन समीक्षा करने एवं जिला कृषि पदाधिकारियों से सम्पर्क कर व्यय प्रतिशत बढ़ाने तथा आवश्यकतानुसार संबंधित जिलों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

कृषि यांत्रिकरण योजना के नोडल पदाधिकारी–सह– संयुक्त निदेशक, अभियंत्रण द्वारा बताया गया कि कुल 180.00 करोड़ रूपये के विरूद्ध आज तक 27.9149 करोड़ रूपये ही व्यय हो सका है, जो 15.5 प्रतिशत है, जिसपर असंतोष व्यक्त करते हुए हर सम्भव प्रयास कर व्यय का प्रतिशत बढ़ाने का निदेश दिया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 134.49951 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के विरूद्ध कुल 68.636836 करोड़ रूपये का आबंटन निर्गत हुआ है तथा 4.7704 करोड़ रूपये व्यय हुआ है, जो 2.5 प्रतिशत है। इसपर असंतोष व्यक्त करते हुए प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

समीक्षोपरांत यह स्पष्ट हुआ कि आजतक कुल 591.0548 करोड़ रूपये ही व्यय हुआ है, जो 24.59 प्रतिशत है, जिसे तीव्र गति से बढ़ाने हेतु सभी नोडल पदाधिकारियों को निदेशित करते हुए सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

16.1.2018

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पी.पी.एम. 48/2017 231/कृ०, पटना, दिनांक 17-01-2018

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी योजनाओं के नोडल पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

16.1.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पी.पी.एम. 48/2017 231/कृ०, पटना, दिनांक 17-01-2018

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

16.1.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।